दै. देशबंधु, भोपाल

- 3 JAN 2015

नीति आयोग के गठन का स्वागत

सही अर्थों में रखी गई अब संघीय ढांचे की नींव

भोपाल, देशबन्धु

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना आयोग के स्थान पर भारत योजना आयोग की जगह नीति आयोग के गठन के फैसले को स्वागत करते हुए कहा है कि 1991 के बाद उदारीकरण के दौर में योजना आयोग की प्रासंगिकता खत्म हो चली थी, इस दौर में नीति आयोग आवश्यक हो गया था। श्री चौहान ने नववर्ष की छुटि्टयां मनाकर लौटने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किए गए नीति आयोग के गठन से भारत के रूपांतरण की विकास प्रक्रिया में सही अर्थों में संघीय ढांचे की नींव रखी गई है।

मुख्यमंत्री ने अपने ब्लॉग और ट्वीटर पर कहा कि एक जनवरी 2015 की नई सुबह भारत ने सहकार और लोकतांत्रिक मूल्यों आधारित विकास के नए युग में आंखें खोली हैं। यह परिवर्तन भारत योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग के रूप में सामने आया है। श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के चहुंमुखी विकास के लिए जिस योजना आयोग का गठन किया था, वह उस दौर की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में था। आजादी के बाद देश का जो विकास हुआ, उसमें आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकास के नियोजन और योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में योजना आयोग ने काफी हद तक अच्छा काम किया, लेकिन बीते कुछ दशक में, विशेष कर 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद योजना आयोग के वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व की प्रासांगिकता लगातार खत्म होती चली गई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न प्रदेश में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। यह बात लगातार महसूस ■ शेष पृष्ठ 8 पर

सही अर्थों में रखी... की जा रही थी कि केंद्र में सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों के संवर्धन में आयोग के राज्यों के साथ राजनैतिक आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह सहायक होने लगे थे। धनराशि के आवंटन में इसी कारण राज्यों के साथ भेदभाव की बात तीव्रता से महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना आयोग की कार्य-प्रणाली में लोकतांत्रिक भावना का अभाव हो गया था। योजना निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा रस्मी हो गई थी। योजनाएं केंद्र से बनाकर राज्यों को भेजी जा रही थीं, इनमें राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, एतिहासिक और सांस्तिक विशिष्टताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। इसी कारण योजनाओं का वांछित लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लगातार यह बात अनेक मंचों से कही कि जिस तरह हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती, उसी तरह हर राज्य के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के विषय में यह बात ज्यादा लागू होती है। उन्होंने ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग बनाया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका गठन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श और उनके सुझाव लेकर किया गया है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को जगह मिली है, इससे राज्यों के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी।